एमएसएमई इकाइयों के लिए 16 जिलों में खुलेंगे 17 सीएफसी

लखनऊ। प्रदेश के 16 जिलों में एमएसएमई इकाइयों के लिए 17 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना होगी। केंद्र सरकार के सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत इस पर 155.95 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे इकाइयों को विनिर्माण, मार्केटिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग लैब, कच्चा माल और बैंक से संबंधित सुविधाएं मिलेंगी।

केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव, अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने दी जानकारी

अपर मुख्य सचिव एमएसएमई डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि क्लस्टर आधारित विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को 17 परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं। क्लस्टर योजना के तहत 20 करोड़ तक की परियोजनाएं ली जा सकती हैं। नक्सल प्रभावित व महत्वाकांक्षी जिलों, 50 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म इकाइयों, महिला, एससी और एसटी स्वामित्व वाली इकाइयों वाले जिलों में सीएफ सी की स्थापना के लिए केंद्र सरकार 90 फीसदी तक अनुदान देती है।

उन्होंने बताया कि झांसी में दो क्लस्टर प्रोसेसिंग पैकेजिंग मसाले ग्रेस और रानीपुर हैंडलूम क्लस्टर बनेंगे। बाराबंकी में चिकनकारी, गाजीपुर में जूल वाल हैंगिंग, चंदौली में पूर्वांचल एग्रो इंडस्ट्रीज, वाराणसी में हाइटेक सिल्क बीविंग एंड डिजाइन क्लस्टर बनेगा। सोनभद्र में कारपेट एवं दरी, संतकबीरनगर में ब्रास बेयर यूटेंशिल, गोरखपुर में टेराकोटा और पॉटरी, लखीमपुर खीरी में चिकनकारी, बदायूं में जरी-जरदोजी और मुरादाबाद में वुडेन प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास होगा। मेरठ में लेदर गुड्स, संभल में वुड प्रोसेसिंग एंड प्रोडेक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आजमगढ़ में जूट रोप यार्न, गौतमबुद्धनगर में प्लास्टिक और सहारनपुर में लेदर फुटवियर क्लस्टर की स्थापना होगी। ब्यूरो